भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1937
उत्तर देने की तारीख-17/12/2025

एनएएसी रेटिंग में विसंगतियां

1937 **श्री येरेम वेंकट सुब्बा रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा अनुकूल ग्रेड या अन्य उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के अधिकारियों या निरीक्षण टीमों को रिश्वत देने का कोई मामला/घटना सरकार के समक्ष आई है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनएएसी अधिकारियों तथा ऐसे संस्थानों/विश्वविद्यालयों पर अब तक संस्थान-वार क्या कार्रवाई की गई है; और
(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार कौन-से निवारक उपाय करने जा रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ .सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ग): राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने अपने मूल्यांकन और प्रत्यायन (ए एंड ए) प्रोटोकॉल को सख्त करने हेतु महत्वपूर्ण उपाय किए हैं और विश्वसनीयता बढ़ाने, डेटा प्रबंधन को सुरक्षित करने और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए सुधारात्मक और निवारक उपायों की एक श्रृंखला लागू की है। इनमें 2-3 महीने पहले के बजाय 15 दिन से एक महीने पहले सहकर्मी टीमों को अंतिम रूप देना, कॉलेजों के लिए यात्राओं को ऑनलाइन बनाना और विश्वविद्यालयों के लिए हाइब्रिड बनाना और बैठकों की कार्यवाही को रिकॉर्ड करना, एनएएसी द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के परिणामों की जांच और पुन: पुष्टि करना आदि शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन को सुदृढ़ करने के लिए, भारत सरकार ने डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति ने एनईपी, 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप कार्यनीतिक सुधारों की शुरूआत और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणालियों के माध्यम से एचईआई के अनुमोदन, प्रत्यायन और रैंकिंग के लिए एक सरल, विश्वास आधारित, उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर विचार किया। इसने मान्यता पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी विचार किया। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस समिति की रिपोर्ट http://naac.gov.in/images/docs/DrRadhakrishnanCommittee-FinalReport.pdf
पर उपलब्ध है।

स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद उत्कृष्टता की दिशा में प्रगति करने के लिए एचईआई को सक्षम बनाने हेतु दो चरणों – बेसिक/बाइनरी प्रत्यायन की शुरूआत और उसके बाद परिपक्वता आधारित श्रेणीबद्ध स्तरों (एमबीजीएल) में सुधारों को कार्यान्वित कर रहा है। एनएएसी ने उच्च शिक्षा अधिकारियों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए नई प्रत्यायन पद्धति के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए हैं और परामर्श पर ध्यान केंद्रित किया है।

*****